**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग**

**राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3371**

**26 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए**

**शांति मिशनों के लिए उपस्कर**

**3371. श्री अमर शंकर साबले :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगो और दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अंग के रूप में तैनात भारतीय सेना के पास उपस्करों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) शांति मिशन में भारत के योगदान हेतु संयुक्त राष्ट्र से सहज रूप में प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए इस मामले में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) से (ग) जी, हां । वर्तमान में, दोनों मिशन क्षेत्रों में कुछ उपस्करों की कमी मौजूद है । यह कमी मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हैः-

(i) बहु-अंतर-महाद्वीपीय एजेंसियों और सरकारों की भागीदारी ।

(ii) संयुक्त राष्ट्र द्वारा समझौता ज्ञापन (एमओयू) में निरंतर परिवर्तन ।

(iii) मिशन क्षेत्रों में दूरस्थ और गैर-विकसित भू-भाग के कारण त्वरित मिशन क्षेत्र की अधिप्राप्ति के लिए स्थानीय संसाधनों की कम उपलब्धता होती है ।

सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय निम्न प्रकार हैं:-

1. जनवरी, 2017 में मिशन क्षेत्र में वृहत् उपस्कर की अधिप्राप्ति संबंधी नीति प्रतिपादित की गई ।
2. मिशन क्षेत्रों में अतिरिक्त ब्रिक अनुरक्षित की गई है ।
3. मिशन क्षेत्र में 10 प्रतिशत अतिरिक्त उपस्कर की तैनाती की गई है (आवधिक रूप से पुनः पूर्ति) ।
4. डीएफपीडीएस 16 में शामिल अनुसूची 25 - उप-सेनाध्यक्ष (वीसीओएएस) को वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं ।
5. एयर कार्गो के द्वारा मिशन क्षेत्र में गोलाबारूद का आवधिक रूप से हवाई परिवहन ।
6. मिशन क्षेत्र में छोटे उपस्कर सहित कलपुर्जों की अधिप्राप्ति हेतु सैन्य-दल कमांडरों की शक्तियों में वृद्धि ।

\*\*\*\*\*